

## द बगि पकिचर/वशेष/इन-डेपथ: SC-ST एक्ट पर वविद क्यों?

### संदर्भ एवं पृष्ठभूमि

अनुसूचति जाति और अनुसूचति जनजाति अधिनियम (SC-ST Act) पर सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले को लेकर दलति समुदाय में काफी आक्रोश है। न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि इस कानून में केवल प्राथमिकी के आधार पर जो गरिफ्तारी होती है, वह गलत है। केंद्र ने इस नरिणय के वरिध में पुनर्वचिार याचिका दायर की, लेकिन न्यायालय ने अपने फैसले पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा, "एससी-एसटी एक्ट को तो हाथ भी नहीं लगाया गया है, केवल नरिदोषों को बचाने की व्यवस्था करते हुए फैसले में संतुलन कायम किया गया है।" दूसरी ओर, दलति संगठनों का मानना है कि इस फैसले के बाद उनके खलिाफ अत्याचार के मामले और बढ़ जाएंगे। न्यायालय के इस फैसले के खलिाफ दलति संगठनों ने भारत बंद आहूत किया जिसमें जान-माल की व्यापक क्षति हुई।

यह अधिनियम 11 सतिंबर, 1989 को अधिनियमित किया गया था और 30 जनवरी, 1990 से जम्मू-कश्मीर को छोड़कर संपूरण भारत में लागू है।

### मामला क्या है?

सर्वोच्च न्यायालय का यह नरिणय डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य और एएनआर मामले में आया है। मामला 2009 का है...महाराष्ट्र के सातारा जलि के गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज में एक दलति कर्मचारी ने प्रथम श्रेणी के दो अधिकारियों के खलिाफ इस कानून के तहत मामला दर्ज कराते हुए अपने वरिध अधिकारियों पर वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में उसके खलिाफ अपमानजनक टपिपणी करने का आरोप लगाया। इसके बाद पुलसि अधिकारी ने जाँच के लिये उच्चधिकारियों से लखिति नरिदेश मांगे, लेकिन इंस्टीट्यूट के प्रभारी डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन ने लखिति में कोई नरिदेश नहीं दिया।

तब दलति कर्मचारी ने सुभाष महाजन के खलिाफ शकियात दर्ज कराई। सुभाष महाजन ने बॉम्बे उच्च न्यायालय से FIR रद्द करने की अपील की, जिसे नामंजूर कर दिया गया। इसके बाद सुभाष महाजन ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि किसी अनुसूचति जाति के व्यक्ती के खलिाफ ईमानदार टपिपणी करना अपराध हो जाएगा तो सामान्य कामकाज कैसे चलेगा। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त फैसला देते हुए उनके खलिाफ FIR हटाने के नरिदेश दिये। न्यायालय ने एससी-एसटी एक्ट के तहत तत्काल गरिफ्तारी पर रोक लगाते हुए आदेश दिया कि गरिफ्तारी न की जाए, बल्कि अग्रमि जमानत मंजूर की जाए।

(टीम दृष्टि इनपुट)

- सर्वोच्च न्यायालय के इस नरिणय को समझना होगा, जिसके बारे में उसका कहना है कि जो इसका वरिध कर रहे हैं उन्होंने फैसला पढ़ा ही नहीं है।
- शीर्ष न्यायालय ने कहा कि उसने एससी-एसटी एक्ट के प्रावधानों को छुआ भी नहीं है, केवल तुरंत गरिफ्तार करने की पुलसि की शक्तियों पर लगाम लगाई है।
- इस मामले में केस दर्ज करने, मुआवजा देने के प्रावधान जस-के-तस बने हुए हैं।
- गरिफ्तार करने की शक्ति आपराधिक दंड संहति से आती है एससी-एसटी कानून से नहीं और न्यायालय ने इस प्रक्रियात्मक कानून की व्याख्या की है, एससी-एसटी एक्ट की नहीं।
- नरिदोषों को सजा नहीं मलिनी चाहिये और न्यायालय ने उन नरिदोष लोगों की चति की बात कही जो जेलों में बंद हैं।

### क्या है न्यायालय का फैसला?

- अगर किसी व्यक्ती के खलिाफ कानून के अंतर्गत मामला दर्ज होता है तो शुरुआती जाँच की जाए, जिसे सात दिनि में पूरा किया जाए।
- शुरुआती जाँच हो या मामला दर्ज कर लिया गया हो, अभयिक्त की गरिफ्तारी जरूरी नहीं है।
- यदि अभयिक्त सरकारी कर्मचारी है तो उसकी गरिफ्तारी के लिये उसे नयिक्त करने वाले अधिकारी की सहमत जरूरी होगी।
- अगर अभयिक्त सरकारी कर्मचारी नहीं है तो गरिफ्तारी के लिये एसएसपी की सहमत जरूरी होगी।
- एससी-एसटी एक्ट की धारा 18 में अग्रमि जमानत की मनाही है, लेकिन अदालत ने अपने आदेश में अग्रमि जमानत की इजाजत देते हुए कहा कि पहली नजर में अगर ऐसा लगता है कि कोई मामला नहीं है या जहाँ न्यायिक समीक्षा के बाद लगता है कि कानून के अंतर्गत शकियात में दुर्भावना है, वहाँ अग्रमि जमानत पर संपूरण रोक नहीं है।
- अदालत ने कहा कि एससी-एसटी एक्ट का यह मतलब नहीं कि जाति व्यवस्था जारी रहे क्योंकि ऐसा होने पर समाज में सभी को साथ लाने में और संवैधानिक मूल्यों पर असर पड़ सकता है। संवैधानिक जाति या धर्म के भेदभाव के समानता की बात कहता है।
- इस कानून को संसद ने इसलिये नहीं बनाया था कि किसी को बलैकमेल करने या निजी बदले के लिये इसका इस्तेमाल किया जाए। इसका उद्देश्य यह नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों को काम करने से रोका जाए। हर मामले में (झूठे और सही दोनों) अग्रमि जमानत को मना कर दिया गया तो नरिदोष लोगों को बचाने वाला कोई नहीं होगा।

- अदालत ने यह भी कहा कि अगर किसी के अधिकारों का हनन हो रहा हो तो वह नषिक्रयि नहीं रह सकती। ऐसे में यह ज़रूरी है कि मूल अधिकारों के हनन और नाइसाफी को रोकने के लिये नए साधनों और रणनीति का इस्तेमाल हो।
- एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज होने वाले केसों में अग्रिम जमानत को भी मंजूरी दे दी गई, जबकि मूल कानून में अग्रिम जमानत की व्यवस्था नहीं की गई है।
- दर्ज मामले में गरिफ्तारी से पहले डपिटी एसपी या उससे ऊपर के रैंक का अधिकारी आरोपों की जाँच करेगा और फरि कार्रवाई होगी।
- एफआईआर दर्ज होने से पहले भी ज्यादती का शिकार हुए कथित पीड़ित को मुआवज़ा दिया जा सकता है।
- न्यायालय ने केवल 7 दिन की सीमा तय की है, जिसके भीतर आरोपों की जाँच पूरी कर ली जाए।
- सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में 2015 के एनसीआरबी (National Crime Record Bureau) के डेटा का उल्लेख किया जिसके अनुसार 15-16% मामलों में पुलिस ने जाँच के बाद क्लोज़र रिपोर्ट फाइल कर दी।
- अदालत में गए 75% मामलों को या तो खत्म कर दिया गया, या उनमें अभियुक्त बरी हो गए, या फरि उन्हें वापस ले लिया गया।

मानवाधिकार संगठन हमेशा से यह कहते रहे हैं कि यदि किसी भी गैर-नृशंस अपराध में केवल FIR के आधार पर गरिफ्तारी का प्रावधान है, तो उसका दुरुपयोग होना नश्चित है। दहेज वरिधी कानून इसकी जीवंत मसाल है और ऐसा ही दुरुपयोग एससी-एसटी एक्ट के कुछ मामलों में भी होता ही होगा। लेकिन हमें दलति समुदाय की पीड़ा को भी समझना होगा। आज़ादी के इतने साल बाद भी उन्हें सामाजिक स्तर पर जसि भेदभाव और प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है, वह किसी भी सभ्य कहलाने वाले समाज में स्वीकार्य नहीं हो सकता। जसि दिन भारत बंद का आयोजन हुआ, उसी दिन अखबारों में यह खबर थी कि एक दलति युवा घोड़ी पर चढ़कर अपनी शादी के लिये जाना चाहता है और गाँव में उच्च जातियों के लोगों को यह स्वीकार नहीं। प्रशासन भी उसकी मदद में असमर्थ था।

(टीम दृष्टि इनपुट)

### एनसीआरबी के आँकड़ों के अनुसार...

- देश में प्रत्येक 15 मिनट में दलति उत्पीड़न की एक घटना सामने आती है
- प्रतदिनि 6 दलति महिलाएँ दुषकर्म का शिकार होती हैं
- 2007-2017 के दशक में देशभर में दर्ज दलति उत्पीड़न के मामलों में 66% की वृद्धि हुई

देश में दलति सदियों से कई तरह की मनोवैज्ञानिक हसिा को झेलते आए हैं। ऐसे में, उन्हें एससी-एसटी एक्ट एक औज़ार की तरह लगता है, जो कई तरह की मानसिक हसिा से उनका बचाव कर सकता है। इसलिये इस प्रावधान को हल्का बनाया जाना उन्हें किसी भी तरह से स्वीकार नहीं।

### राष्ट्रीय अनुसूचति जात/जनजात आयोग

अनुसूचति जातियों और अनुसूचति जनजातियों के हतियों की रक्षा तथा उनके कल्याण हेतु उपाय सुझाने के लिये पहले एक ही आयोग था, जसिका नाम राष्ट्रीय अनुसूचति जात एवं अनुसूचति जनजात आयोग था। बाद में संवधान (89वाँ संशोधन) अधनियम 2003 के माध्यम से अनुच्छेद 338 को संशोधति कर तथा संवधान में नया अनुच्छेद 338ए शामिल करके राष्ट्रीय अनुसूचति जनजात आयोग की स्थापना की गई। इस संवधान संशोधन से पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अनुसूचति जात एवं अनुसूचति जनजात आयोग की जगह दो नए आयोग--राष्ट्रीय अनुसूचति जात आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचति जनजात आयोग 19 फरवरी, 2004 को बनाए गए।

(टीम दृष्टि इनपुट)

### अनुसूचति जात और अनुसूचति जनजात अधनियम

अनुसूचति जात और अनुसूचति जनजात (अत्याचार नवारण) अधनियम, 1989 भारतीय समाज को परंपरागत वशिवासों के अधानुकरण तथा अतार्ककिक लगाव से मुक्त करने के उद्देश्य से लाया गया था। लेकिन दलतियों के हतियों की रक्षा के लिये सबसे पहले 1955 में असंपृश्यता (अपराध नवारण) अधनियम लाया गया था, जसिकी कमयियों एवं कमज़ोरयियों के कारण सरकार को इसमें व्यापक सुधार करना पड़ा। सुधारों और संशोधनों के बाद 1976 से इस अधनियम का नागरिक अधिकार संरक्षण अधनियम के रूप में पुनर्गठन किया गया।

अनुसूचति जातियों एवं अनुसूचति जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के अनेक उपाय करने के बावजूद उनकी स्थिति दयनीय बनी रही। उन्हें अपमानति एवं उत्पीड़ति किया जाता रहा। उन्होंने जब भी असंपृश्यता के वरिद्ध अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहा, उन्हें दबाने एवं आतंकति करने जैसी घटनाएँ सामने आईं। अनुसूचति जातियों एवं अनुसूचति जनजातियों का उत्पीड़न रोकने तथा दोषयियों पर कार्रवाई करने के लिये वशिष अदालतों के गठन को आवश्यक समझा गया। उत्पीड़न के शिकार लोगों को राहत, पुनर्वास उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती थी।

इसी पृष्ठभूमि में अनुच्छेद 17 के तहत अनुसूचति जात और अनुसूचति जनजात (अत्याचार नवारण) अधनियम, 1989 बनाया गया था। इस अधनियम का स्पष्ट उद्देश्य अनुसूचति जात एवं अनुसूचति जनजात समुदाय को सक्रयि प्रयासों से न्याय दलिताना था ताकि समाज में वे गरमि के साथ रह सकें। इस अधनियम में 2015 में संशोधन कर इसके प्रावधानों को और कठोर बनाया गया। वर्तमान में इसमें पाँच अध्याय और 23 धाराएँ हैं।

### संशोधन के बाद प्रमुख प्रावधान

- अनुसूचति जातियों और अनुसूचति जनजातियों के वरिद्ध कयि जाने वाले नए अपराधों में नमिनलखिति शामिल हैं:
- सरि और मूँछ के बालों का मुंडन कराना
- अत्याचारों में समुदाय के लोगों को जूते की माला पहनाना

- सचिवाई सुवधियाँ तक जाने से रोकना या वन अधिकारों से वंचित रखना
- मानव और पशु नरककाल को नपिटाने और लाने-ले जाने के लिये बाध्य करना
- कब्र खोदने के लिये बाध्य करना
- सरि पर मैला ढोने की प्रथा का उपयोग और अनुमति देना
- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं को देवदासी के रूप में समर्पित करना
- जातसूचक शब्द कहना
- जादू-टोना अत्याचार को बढ़ावा देना
- सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार करना
- चुनाव लड़ने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को नामांकन दाखल करने से रोकना
- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं को वस्त्रहरण कर आहत करना
- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के किसी सदस्य को घर-गाँव और आवास छोड़ने के लिये बाध्य करना
- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की पूजनीय वस्तुओं को वरिपति करना
- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य के वरिद्ध यौन दुरव्यवहार करना, यौन दुरव्यवहार भाव से उन्हें छूना और भाषा का उपयोग करना

10 वर्ष से कम की सज़ा का प्रावधान वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को आहत करने, उन्हें पीड़ा पहुँचाने, धमकाने और उपहरण करने जैसे अपराधों को अधिनियम में अपराध के रूप में शामिल किया गया। इसे पूर्व अधिनियम के तहत अनुसूचित जात और जनजात के लोगों पर किये गए अत्याचार के मामलों में 10 वर्ष और उससे अधिक की सज़ा वाले अपराधों को ही अपराध माना जाता था।

मामलों को तेज़ी से नपिटाने के लिये अत्याचार नविवरण अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराधों में वशिष रूप से मुकदमा चलाने के लिये वशिष अदालतें बनाना और वशिष लोक अभियोजक को नरिदषिट करना।

वशिष अदालतों को अपराध का प्रत्यक्ष संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान करना और जहाँ तक संभव हो आरोप-पत्र दाखल करने की तथिसे दो महीने के अंदर सुनवाई पूरी करना।

### अन्य संवधानिक प्रावधान

- संवधान के अनुच्छेद 46 में राज्य से अपेक्षा की गई है कविह समाज के कमज़ोर वर्गों, वशिषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हतियों का ध्यान रखते हुए उन्हें सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से संरक्षित रखेगा।
- शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 15(4) में किया गया है।
- पदों एवं सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान संवधान के अनुच्छेद 16(4), 16(4क) और 16(4ख) में किया गया है।
- मूल अधिकारों के अलावा अनुच्छेद 330, 332 और 335 में केंद्र और राज्यों की वधायिकाओं में इन समुदायों के लिये वशिष प्रतनिधित्व एवं सीटों के आरक्षण के लिये तात्कालिक प्रावधान हैं।
- अनुच्छेद 338 से 342 और संवधान की पांचवीं और छठी अनुसूची अनुच्छेद 46 में दिये गए लक्ष्यों हेतु वशिष प्रावधानों के संबंध में कार्य करते हैं।

(टीम दृष्टि इनपुट)

**नषिकर्ष:** अनुसूचित जात एवं अनुसूचित जनजात (अत्याचार नविवरण) अधिनियम, 1989 अनुसूचित जात एवं अनुसूचित जनजात के लोगों के वरिद्ध किये गए अपराधों के नविवरण के लिये है। यह अधिनियम ऐसे अपराधों के संबंध में मुकदमा चलाने तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों के लिये राहत एवं पुनर्वास का प्रावधान करता है।

इस अधिनियम के तहत किये गए अपराध सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला आने से पहले तक गैर- ज़मानती, संज्ञेय तथा अशमनीय थे। न्यायालय का मानना है कि इस कानून में इन प्रावधानों का दुरुपयोग हो रहा है, अतः संतुलन कायम करने और पुलसि की शक्तियों कम करने के लिये ऐसा किया गया है। यह पहली बार नहीं है जब सर्वोच्च न्यायालय के किसी नरिणय का इस प्रकार सडकों पर वरिध हुआ। हाल ही में फलिम 'पदमावत' को लेकर भी ऐसी ही उग्र स्थिति बन गई थी। आदर्श स्थिति तो यह होती और स्वस्थ लोकतंत्र का तकाज़ा भी यही है कि ऐसे फैसलों को या तो स्वीकार कर लिया जाता या उनके खिलाफ पुनर्वचार याचिका दायर की जाती, जैसा कि सरकार ने किया भी। लेकिन इस सवाल का जवाब कभी सरल नहीं रहा कि यदि किसी प्रावधान का दुरुपयोग होता है, तो क्या एकमात्र वकिल्प उसे हटाना है?